

# UPSC-CSE 2027/28



# DAILY CURRENT AFFAIRS

 **ONE STOP SOLUTION**

By **Faiyaz Sir**



**26**  
**SEPTEMBER**



**COMPLETE  
COVERAGE**



**EXAM  
FOCUSED**



**ANALYSIS  
MADE EASY**



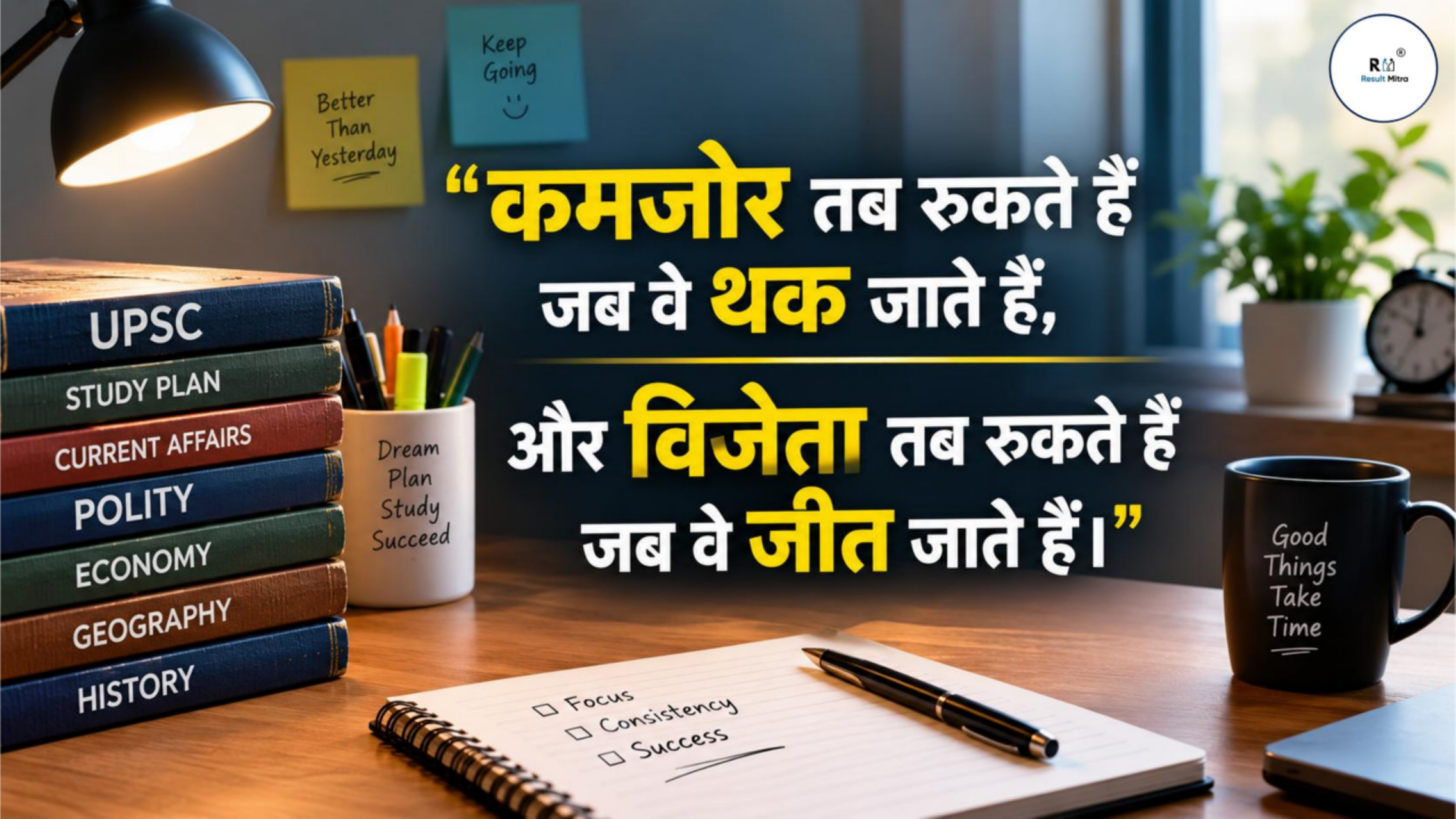
**STATIC + CURRENT  
INTEGRATION**



**STAY AHEAD  
STAY PREPARED**



“**कमजोर** तब रुकते हैं  
जब वे **थक** जाते हैं,  
**और विजेता** तब रुकते हैं  
जब वे **जीत** जाते हैं।”





# आज क्या पढ़ेंगे?

- UNGA
- India's Nuclear Policy
- महत्वपूर्ण तथ्य

1.R → Not in  
non-UNGA

1.R + S & T + Polity  
↳

## Overweight and weak

The UN is unwieldy, and needs to move away from superpower hegemony

**T**he 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) could have been written off as just another year, with another set of speeches delivered on the global multilateral stage. However, this year, the UN's annual Summit has a unique sense of urgency. This is UN Secretary-General (UNSG) António Guterres's final session, after a tenure marked by a record number of global crises, conflicts, pandemics, climate disasters and the advent of a dangerous age of Artificial Intelligence. Not since the Second World War have there been so many conflicts; one study recorded more than 65 conflicts across 35 countries in 2025, the highest since 1946. Growing polarisation on every major issue, wars by global superpowers in violation of the UN charter, nuclear threats and the imposition of unilateral and illegitimate sanctions have weakened the UN, which at 81 seems overweight, weak and unrepresentative of the world. This makes it an important year for the world to unite in favour of a strengthened and reformed UN while choosing the next UNSG to guide that process over the next decade. This is an important year for South Asia too, with the election of Ban-

gladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman as the President of the UNGA's 81st session; he will oversee the UNSG's selection. It was disappointing that the world's most powerful leaders and those at the heart of the conflicts in Ukraine, Gaza and the Persian Gulf failed to suggest solutions for the future. U.S. President Donald Trump spoke about the possible "annihilation" of Iran, and defended U.S. actions in Venezuela. Much to India's chagrin, he again claimed to have negotiated peace in conflicts including the 2025 India-Pakistan four-day war. Iranian President Masoud Pezeshkian referred to the U.S. and Israel as "murderers, terrorists and assassins". The Russian President skipped the session, while the U.S. denied visas to the Palestinian delegation. An initiative led by the European Union and a few other countries, co-sponsored by India, to build a Partnership for Multilateralism (P4M) beyond superpower hegemony is well-meaning, but was drowned out by the rancour at this year's UNGA.

For India, this year was significant as the Narendra Modi government launched a campaign for a second two-year non-permanent term in the UN Security Council in 2028-29. It was therefore surprising that Mr. Modi decided to skip the UNGA speech this year, and the multilateral summits on the side-lines, fresh from his hosting of the Delhi BRICS Summit. India's voice, of a balancing power that speaks for a rules-based international order based on the UN Charter, diplomacy and dialogue, is needed more than ever amidst the global warmongering.

*Editorial*



- **संयुक्त राष्ट्र (United Nations / UN)** दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना **24 अक्टूबर 1945** को द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के समाप्त होने के बाद हुई थी, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा वैश्विक युद्ध न हो।
- इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

### 1. मुख्य उद्देश्य

- **वैश्विक शांति और सुरक्षा:** दुनिया भर में युद्धों को रोकना और विवादों को कूटनीति/बातचीत के जरिए सुलझाना।
- **मानवाधिकारों की रक्षा:** दुनिया में हर नागरिक के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- **मानवीय सहायता:** आपदाओं, युद्ध या महामारी के समय प्रभावित देशों को राहत सामग्री पहुँचाना।
- **सतत विकास (Sustainable Development):** गरीबी, भुखमरी और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटना।

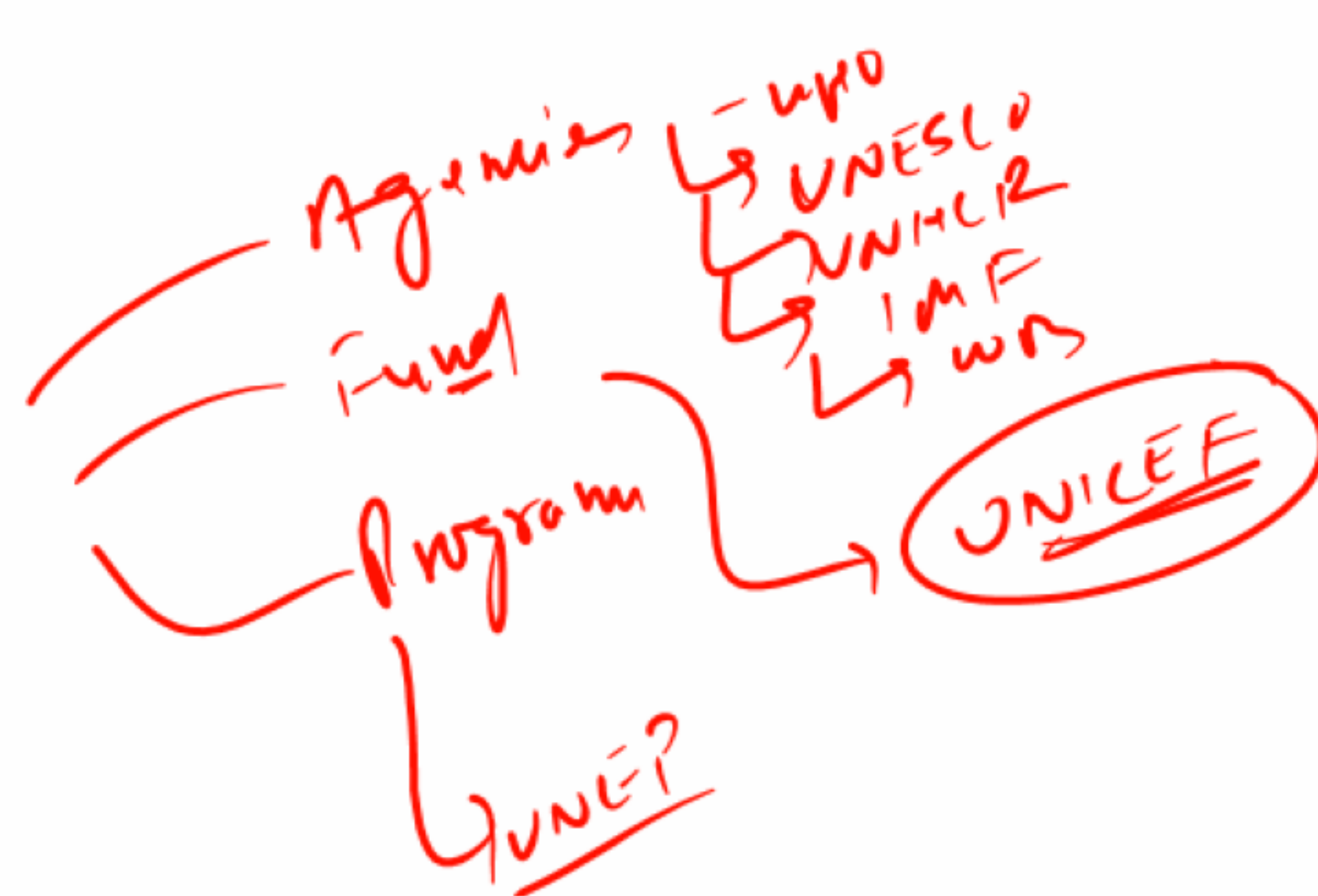
### 2. संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग

- **महासभा (UN General Assembly - UNGA):** यह UN का मुख्य विचार-विमर्श अंग है, जिसमें दुनिया के सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है।
- **सुरक्षा परिषद (UN Security Council - UNSC):** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार। इसमें **5 स्थायी सदस्य** (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस) और **10 अस्थायी सदस्य** होते हैं।
- **आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC):** वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर काम करती है।
- **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ):** नीदरलैंड्स के 'द हेग' में स्थित, यह देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है।
- **सचिवालय (Secretariat):** UN का प्रशासनिक अंग, जिसका नेतृत्व महासचिव (Secretary-General) करते हैं।
- **न्यासिता परिषद (Trusteeship Council):** (वर्तमान में यह निष्क्रिय है, इसका काम 1994 में पूरा हो गया था)।



### 3. प्रमुख विशेष एजेंसियां

- UN कई विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करता है, जैसे:
- **WHO** (विश्व स्वास्थ्य संगठन) - स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
- **UNICEF** (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) - बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए।
- **UNESCO** - शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के संरक्षण के लिए।
- **UNHCR** - शरणार्थियों की सहायता के लिए।



### 4. मुख्यालय और सदस्यता

- मुख्यालय: न्यू यॉर्क, अमेरिका।
- सदस्य देश: वर्तमान में 193 देश इसके पूर्ण सदस्य हैं।
- आधिकारिक भाषाएं: 6 भाषाएं (अंग्रेजी, हिंदी के बजाय - अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अंग्रेजी)



## संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र

- **विशेष महत्व:** यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव (UNSG) एंटोनियो गुटेरेस का अंतिम सत्र है।
- **वैश्विक स्थिति:** यह सत्र ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे अधिक संघर्ष (2025 में 35 देशों में 65 से अधिक संघर्ष) दर्ज किए गए।
- **अध्यक्षता:** दक्षिण एशिया के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को UNGA के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, जो अगले महासचिव के चयन की निगरानी करेंगे।

### वैश्विक नेताओं के बयान:

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के संभावित विनाश की बात की और 2025 के भारत-पाकिस्तान चार दिवसीय युद्ध में शांति वार्ता कराने का दावा फिर दोहराया।

- ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इजराइल पर तीखे हमले किए।
- रूस के राष्ट्रपति सत्र में शामिल नहीं हुए और अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को वीजा देने से मना कर दिया।
- **भारत का रुख:** भारत ने 2028-29 के लिए UN सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिए अभियान शुरू किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र को छोड़ दिया।
- **P4M पहल:** यूरोपीय संघ और भारत द्वारा सह-प्रायोजित 'Partnership for Multilateralism' (P4M) पहल का उद्देश्य महाशक्तियों के वर्चस्व से परे बहुपक्षवाद का बढ़ावा देना था।



## UN - संयुक्त राष्ट्र

- संयुक्त राष्ट्र (UN) बोज़िल हो चुका है और इसे महाशक्तियों के वर्चस्व से बाहर निकलने की आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र को भी वैश्विक बहुपक्षीय मंच पर भाषणों के एक और सामान्य वर्ष के रूप में खारिज किया जा सकता था। हालांकि, इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक शिखर सम्मेलन में तात्कालिकता का एक अनूठा भाव है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) एंटोनियो गुटेरेस का यह अंतिम सत्र है, जिनका कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकटों, संघर्षों, महामारी, जलवायु आपदाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के खतरनाक युग की शुरुआत से चिह्नित रहा है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इतने अधिक संघर्ष कभी नहीं देखे गए; एक अध्ययन के अनुसार 2025 में 35 देशों में 65 से अधिक संघर्ष दर्ज किए गए, जो 1946 के बाद सबसे अधिक हैं। हर प्रमुख मुद्दे पर बढ़ता ध्रुवीकरण, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन में महाशक्तियों द्वारा युद्ध, परमाणु धमकियां और एकतरफा व अवैध प्रतिबंधों के कारण संयुक्त राष्ट्र कमजोर हुआ है। 81 साल की उम्र में यह अधिक बोज़िल, कमजोर और दुनिया का प्रतिनिधित्व न करने वाला प्रतीत होता है।
- यह वर्ष दुनिया के लिए एक सशक्त और सुधारित संयुक्त राष्ट्र के पक्ष में एकजुट होने तथा अगले दशक में इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए अगले महासचिव को चुनने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। दक्षिण एशिया के लिए भी यह वर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं; वह UNSG के चयन की निगरानी करेंगे।
- यह निराशाजनक था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता और यूक्रेन, गाजा व फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के संघर्षों के केंद्र में रहने वाले भविष्य के समाधान सुझाने में विफल रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के संभावित "विनाश" (annihilation) की बात कही और वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाइयों का बचाव किया। भारत की नाराजगी के बावजूद, उन्होंने एक बार फिर 2025 के चार दिवसीय भारत-पाकिस्तान युद्ध सहित कई संघर्षों में शांति वार्ता कराने का दावा किया।



- ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इजराइल को "हत्यारा, आतंकवादी और हत्यारा" (murderers, terrorists and assassins) करार दिया। रूसी राष्ट्रपति ने सत्र में भाग नहीं लिया, जबकि अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को वीजा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशों द्वारा शुरू की गई और भारत द्वारा सह-प्रायोजित पहल—महाशक्तियों के वर्चस्व से परे बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी (P4M)—एक अच्छी नीयत से उठाया गया कदम था, लेकिन इस साल के UNGA की कड़वाहट में यह दब गया।
- भारत के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण था क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दूसरे दो-वर्षीय गैर-स्थायी कार्यकाल के लिए अभियान शुरू किया। इसलिए यह आश्चर्यजनक था कि दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के तुरंत बाद, श्री मोदी ने इस वर्ष UNGA के भाषण और उससे इतर बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा न लेने का फैसला किया।
- वैश्विक युद्धोन्माद (warmongering) के बीच भारत की वह आवाज—जो एक संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, कूटनीति और संवाद पर आधारित नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बात करती है—की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।



## प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Question)

- प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र (UN) और हालिया वैश्विक बहुपक्षीय पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर-स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
2. 'पार्टनरशिप फॉर मल्टीलेटरलिज्म' (P4M) पहल का उद्देश्य महाशक्तियों के वर्चस्व से परे बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है।
3. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का अध्यक्ष केवल स्थायी सुरक्षा परिषद के देशों से ही चुना जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

## मुख्य परीक्षा (Mains Question)

- प्रश्न: "वर्तमान वैश्विक संघर्षों और महाशक्तियों के बढ़ते ध्रुवीकरण ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की प्रभावशीलता पर सवाल उठा दिए हैं।" इस कथन के आलोक में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारों की चर्चा कीजिए। भारत के लिए इसमें एक स्थायी/गैर-स्थायी सीट का क्या महत्व है? (250 शब्द)



# Revisiting India's nuclear doctrine without revising it

India's nuclear doctrine has remained largely unchanged for over two decades, even as its security environment has shifted dramatically. Since its operationalisation in 2003, China's military rise has accelerated, Pakistan's nuclear posture has evolved, disruptive technologies have reshaped deterrence, and geopolitical competition has become more multipolar. Yet, the doctrine's core principles – credible minimum deterrence and a declared No First Use (NFU) posture – have endured, albeit with a specific provision retaining the option of nuclear retaliation following a major biological or chemical attack on India or Indian forces. The question is whether a framework crafted for the early 2000s remains fully aligned with the security challenges of the mid-2020s.

**A doctrine for another era, strategic shifts**  
India's nuclear doctrine emerged from the distinct strategic context of the late 1990s. The 1998 Pokhran-II tests established India as a nuclear weapons state, while Kargil (1999) showed that nuclear deterrence did not rule out conventional war. The 1999 Draft Nuclear Doctrine and the Cabinet Committee on Security's January 4, 2003 decision sought to reconcile deterrence with restraint. The 2003 decision operationalised a posture based on credible minimum deterrence, No First Use (NFU) and massive retaliation to a nuclear attack, supported by a survivable second-strike capability and firm civilian control. Judged by its original objectives, the doctrine has provided continuity, predictability and strategic stability for more than two decades. The question is whether the assumptions underpinning it remain stable.

The strategic environment underpinning the framework has changed in three important ways. First, China and Pakistan have grown more strategically aligned. When the doctrine was



**Advitya Madan**

Analyst on geopolitics, international and defence affairs, commanded 15 Punjab in Lebanon under the United Nations Flag, commanded 27 Sector as DIG in Churachandpur, Manipur, and was Brigadier Operational Logistics in HQ Western Command

India's nuclear doctrine faces new strategic, technological and geopolitical challenges

formulated, the two nuclear-armed neighbours posed distinct challenges; today, those challenges are increasingly interconnected. China has expanded and modernised its nuclear forces, strengthened military infrastructure along the Line of Actual Control and deepened defence cooperation with Pakistan. Pakistan has diversified its nuclear capabilities, including tactical nuclear weapons intended to offset India's conventional advantage. India must therefore account for the possibility that pressures from two closely aligned nuclear adversaries could interact during a crisis.

The second shift is technological. Artificial intelligence, cyber capabilities, space-based surveillance, hypersonic weapons and ballistic missile defence are reshaping deterrence by shortening decision-making timelines, increasing the vulnerability of command-and-control networks and complicating assumptions about assured retaliation. These technologies do not invalidate the doctrine's core principles, but they alter the environment in which they must operate. Nuclear deterrence ultimately depends on the alignment of doctrine, capability and survivability.

The third shift is geopolitical. The Indo-Pacific has become a key arena of great-power competition, while the international system has grown more multipolar. U.S.-China rivalry, closer China-Russia coordination and India's expanding partnerships have reshaped the security environment. Nuclear doctrine can no longer be viewed solely through bilateral deterrence; regional crises are increasingly shaped by wider geopolitical competition.

## Review, not revision

Strategic doctrines are policy instruments, not immutable documents. In India's case, a review could examine emerging technologies, command-and-control resilience, second-strike

capabilities and the continuing relevance of existing concepts, including the doctrine's approach to retaliation.

The issue of massive retaliation deserves scrutiny. Pakistan's tactical nuclear weapons were intended to complicate India's response options below the level of strategic exchange. A review could assess whether India's declaratory posture provides sufficient deterrent clarity across nuclear contingencies, without necessarily changing its core principles.

There are, however, reasons for caution. India's doctrine has reinforced its image as a restrained and responsible nuclear power while providing continuity in deterrence. Ambiguity over established principles, particularly NFU, could create uncertainty, encourage adversaries to recalibrate and complicate crisis management. The priority, therefore, should be to strengthen operational capabilities, modernise delivery systems and improve command-and-control resilience rather than reopen declaratory policy.

A review of NFU need not mean abandoning it. It could reaffirm its rationale, clarify its scope and ensure that supporting capabilities remain credible. Reviewing a doctrine is not the same as revising it.

## Building credible capabilities

For India, any doctrinal review should also assess survivability, command and control, intelligence, early warning, cyber resilience and the nuclear triad. The aim should be to ensure that India's declared policy remains backed by credible capabilities in a changing strategic environment, while aligning nuclear policy with its broader diplomatic objectives and strategic autonomy.

Ultimately, a nuclear doctrine is an instrument of statecraft, not an immutable policy. India's commitment to restraint, credible deterrence and responsible nuclear stewardship remains an enduring strategic asset.

*Editorial*

*पि-एम*

*दुनिया में बिना ५ (पाउंडेशन) बिना देश - पाउंडेशन हीयार सम्मेलन*

*काम से पाउंडेशन ५ (पाउंडेशन) हीयार*



- **भारत का परमाणु सिद्धांत (India's Nuclear Doctrine)** भारत की परमाणु नीति की वह रूपरेखा है जो यह तय करती है कि भारत अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कब, कैसे और किस परिस्थिति में करेगा।
- भारत ने मई 1998 में पोखरण-II परीक्षणों के बाद अपने परमाणु सिद्धांतों को तैयार किया था, जिसे जनवरी 2003 में आधिकारिक रूप से घोषित और लागू किया गया। *PM - उद्घाटन वीडियो*
- भारत के परमाणु सिद्धांत के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं:

### 1. पहले उपयोग न करना (No First Use - NFU)

- भारत ने घोषित किया है कि वह किसी भी देश पर पहला परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत परमाणु हथियारों का उपयोग केवल तब करेगा जब भारत या उसकी सशस्त्र सेनाओं पर किसी अन्य देश द्वारा परमाणु हमला किया जाएगा।

### 2. विश्वसनीय न्यूनतम निवारण (Credible Minimum Deterrence)

- भारत का लक्ष्य बड़ी संख्या में परमाणु हथियार इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि केवल उतने ही हथियार और क्षमताएं रखना है जो दुश्मनों को भारत पर हमला करने से रोकने (deterrence) के लिए पर्याप्त हों।

### 3. व्यापक जवाबी कार्रवाई (Massive Retaliation)

- यदि कोई देश भारत पर पहला परमाणु हमला करता है, तो भारत उस पर इतनी प्रचंड और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई करेगा कि हमलावर देश को भारी और असहनीय नुकसान उठाना पड़ेगा।

### 4. गैर-परमाणु राज्यों पर हमला नहीं (Non-Use Against Non-Nuclear States)

- भारत किसी भी ऐसे देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा जिसके पास परमाणु हथियार नहीं हैं।

### 5. रासायनिक और जैविक हमलों का अपवाद (Exception for Biological/Chemical Attacks)

- यदि भारत या भारतीय सेना पर बड़े स्तर पर जैविक (Biological) या रासायनिक (Chemical) हथियारों से हमला किया जाता है, तो भारत के पास परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प खुला रहेगा।

### 6. असैन्य / नागरिक नियंत्रण (Civilian Control)

- परमाणु हथियारों के उपयोग का अधिकार केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नागरिक सरकार यानी पधानमंत्री की अध्यक्षता वाले 'परमाणु कमान प्राधिकरण' (Nuclear Command Authority - NCA) के पास है, सेना के पास नहीं।

*97-445*



## 7. परमाणु हथियार-मुक्त दुनिया का समर्थन

- भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु अप्रसार (Non-proliferation) और वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष एवं भेदभाव-रहित परमाणु निरस्त्रीकरण (Disarmament) का समर्थन करता है।

## न्यूक्लियर ट्राइएड (Nuclear Triad)

- इस नीति को प्रभावी बनाए रखने के लिए भारत के पास न्यूक्लियर ट्राइएड की क्षमता है, जिसका अर्थ है कि भारत जमीन (मिसाइल), हवा (लड़ाकू विमान) और समुद्र (परमाणु पनडुब्बी - जैसे INS अरिहंत) तीनों स्थानों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह क्षमता भारत को 'सेकंड-स्ट्राइक क्षमता' (Second-Strike Capability) प्रदान करती है।



## भारत का परमाणु सिद्धांत (India's Nuclear Doctrine)

- भारत का परमाणु सिद्धांत 2003 में लागू हुआ था, जिसके मुख्य स्तंभ 'नो फर्स्ट यूज़' (NFU) और 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारण' (Credible Minimum Deterrence) हैं। बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के कारण इसमें संशोधन (Revision) की नहीं, बल्कि समीक्षा (Review) की आवश्यकता है।

दुनिया में ऐसे 5 परमाणु देश हैं 2003 - 2026

### 1. परमाणु सिद्धांत में समीक्षा की आवश्यकता क्यों?

- चीन-पाकिस्तान की बढ़ती साठगांठ: चीन अपनी परमाणु क्षमता और LAC पर ढांचागत ढांचा मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने 'सामरिक परमाणु हथियार' (Tactical Nuclear Weapons) विकसित किए हैं। भारत को दोनों मोर्चों के एक साथ सक्रिय होने का खतरा है।
- तकनीकी प्रगति: AI, हाइपरसोनिक हथियार, साइबर खतरे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कारण निर्णय लेने का समय बहुत कम हो गया है और कमांड-एंड-कंट्रोल नेटवर्क पर जोखिम बढ़ गया है।
- इंडो-पैसिफिक की भू-राजनीति: अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के कारण परमाणु निवारण केवल द्विपक्षीय न होकर वैश्विक राजनीति से प्रभावित हो रहा है।

## 'समीक्षा' (Review) बनाम 'संशोधन' (Revision)

- संशोधन की आवश्यकता क्यों नहीं?
  - NFU नीति को पूरी तरह से बदलने या हटाने से क्षेत्र में अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ेगी।
  - भारत की एक "संयमित और जिम्मेदार परमाणु शक्ति" की छवि को नुकसान पहुंचेगा।
- समीक्षा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
  - 'व्यापक जवाबी कार्रवाई' (Massive Retaliation) के रुख को और स्पष्ट करना।
  - न्यूक्लियर ट्राइएड (Nuclear Triad), अर्ली वार्निंग सिस्टम, सेकंड-स्ट्राइक क्षमता और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना।
  - NFU नीति का त्याग किए बिना इसके दायरे और विश्वसनीयता को बढ़ाना।



## प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Question)

प्रश्न: भारत के परमाणु सिद्धांत (India's Nuclear Doctrine) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत की नीति के अनुसार, भारत किसी भी गैर-परमाणु हथियार वाले राज्य के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा।
2. यदि भारत पर रासायनिक या जैविक हथियारों से बड़ा हमला होता है, तो भारत के पास परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प मौजूद है।
3. परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत करने का अंतिम अधिकार सेनाध्यक्ष के पास होता है।

परमाणु हथियारों का उपयोग

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

## मुख्य परीक्षा (Mains Question)

- प्रश्न: "बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल और उभरती प्रौद्योगिकियों के आलोक में, भारत के 'नो फर्स्ट यूज' (NFU) परमाणु सिद्धांत की प्रभावशीलता पर बहस छिड़ गई है।" चर्चा कीजिए कि क्या भारत को अपनी परमाणु नीति में संशोधन करने की आवश्यकता है या केवल इसकी परिचालन क्षमताओं (operational capabilities) को मजबूत करना पर्याप्त होगा? (250 शब्द)



# महत्वपूर्ण तथ्य

## Govt. to hold talks with banks and decide subsidy amount for UPI after charges kick in

UPI - Payment  
MDR - .4%  
P - D → X

## YouTube Homework

T.C.A. Sharad Raghavan  
NEW DELHI

The Merchant Discount Rate (MDR) on UPI transactions will not be enough to cover the cost of running and maintaining the payment platform, and so the government will soon hold discussions with the Indian Banks' Association (IBA) to decide what quantum of the ongoing government subsidy should continue and in what form, sources in the Ministry of Finance have confirmed.

The Ministry of Finance will also coordinate with the IBA on how to ensure that merchants do not pass on the MDR charge to customers. The MDR charge will go live on UPI on October 15, and there is no proposal to delay this date, the sources said. The government has budgeted ₹2,000 crore for the ongoing financial year under its incentive scheme for the promotion of RuPay debit cards and low-value BHIM-UPI transactions.

### Subsidy shifts

The MDR is set to take effect on UPI from **October 15**, and the government is now considering how much subsidy should continue and in what form. It has budgeted **₹2,000 crore** for the incentive scheme in FY2024-25.

| Financial year | BHIM-UPI (₹ crore) | RuPay Debit Card (₹ crore) | Total payout (₹ crore) |
|----------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| FY2021-22      | 957                | 432                        | 1,389                  |
| FY2022-23      | 1,802              | 408                        | 2,210                  |
| FY2023-24      | 3,268              | 363                        | 3,631                  |
| FY2024-25*     | 1,046              | -                          | 1,046                  |

Note: \* FY2024-25 figure is actual expenditure as of November 30, 2023; it is not the final full-year expenditure. The FY2024-25 scheme covered low-value BHIM-UPI transactions only, with an estimated outlay of ₹1,500 crore

Source: Department of Financial Services

ing financial year under its incentive scheme for the promotion of RuPay debit cards and low-value BHIM-UPI transactions.

"The MDR amount that will be collected will not be enough to cover the full cost of UPI," a senior official in the Ministry said on condition of anonymity. "As for the incentive the

government is already providing, we will need to discuss with the IBA on how much should continue and how... We will also be speaking to the IBA in the run-up to October 15 to work out ways in which it can be ensured that the merchants do not pass on the MDR to customers," the official added.

The Finance Ministry will also be speaking to traders and their umbrella body, the Confederation of All India Traders, on the MDR charge and explain to them how most merchants will not be affected, and so should not stop accepting UPI payments.

### Issue for GST Council

Another official said that the Ministry could not "unilaterally" decide on the issue of a levy of Goods and Services Tax on the MDR amount collected by payment processors and banks from merchants.

"UPI is a service, and the MDR is the charge for providing that service to merchants," the second official explained. "As such, that service is taxed under GST. But it is for the GST Council to decide on the rate, how much, whether to exempt and all that. The

Centre cannot unilaterally take those actions."

The second official clarified that the GST Council meeting on October 7 will be related to process reforms rather than "any sort of rate issue".

Both officials confirmed that the Ministry of Petroleum will be engaging with the petroleum dealers and their associations to work on their issues regarding MDR. The dealers' associations have voiced their concerns and have asked for a waiver.

"The MDR issue for the dealers is that it will impact their profit margins, and so they have used this as a reason to ask for a review of the margin amount that is decided by them and the Petroleum Ministry," one of the officials explained.

There is no proposal to waive MDR for them, the officials added.

## ➤ Payment and Settlement

Act 2007 -

➤ NPCI

➤ UPI

➤ MDR

UPI - Payment  
MDR - .4%  
P - D → X  
Bank  
ATM  
15 October  
2024

MDR  
2024/15  
2026  
15 Oct-24  
2024  
4% MDR



# महत्वपूर्ण तथ्य



## Four Nagas killed on Manipur border by Myanmar extremists

**The Hindu Bureau**  
GUWAHATI

Assailants allegedly belonging to Myanmar-based armed groups killed four Nagas from Pilog village in Manipur's Kamjong district on Thursday.

"A Kuki terror group armed with sophisticated weapons crossed the river Namyang from Phailen Kuki village of Myanmar and launched a violent attack on Pilog civilians," said the Working Committee of the Tangkhul Naga Long (WC-TNL), the top body of the Tangkhul community.

Pilog village is near India's border with Myanmar.

In a statement on Friday, the WC-TNL said the assailants shot dead two residents in the vicinity of the village, while the two others were taken away to

Phailen and killed. It claimed that members of the Kuki National Army-Burma and Kuki elements backed by Myanmar-based People's Defence Force carried out the attack.

"Five residents were keeping watch at Pilog settlement area when the incident took place. One managed to escape and was rescued by a team of Tangkhul civil society organisations," the organisation said.

### Third attack

The WC-TNL said this was the third such attack on Naga villagers along the border in Kamjong district.

Despite repeated attacks, the State government and border guards remained "lackadaisical", failing to protect vulnerable villagers living along the border, it said.

## YouTube Homework

- Manipur Location – मैजो लिङ
- Siliguri Corridor – Chicken's Neck



# महत्वपूर्ण तथ्य



- मणिपुर संकट (Manipur Crisis) पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में जारी एक गंभीर जातीय और सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष है, जो मुख्य रूप से **मैतेई (Meitei)** और **कुकी-जो (Kuki-Zo)** समुदायों के बीच मई 2023 से शुरू हुआ।
- इस संकट के मुख्य पहलुओं को आसान शब्दों में समझा जा सकता है:

2023-2026

## 1. संकट की पृष्ठभूमि और मुख्य कारण

- ST दर्जा और अदालती आदेश:** विवाद की तात्कालिक वजह मणिपुर उच्च न्यायालय का वह सुझाव था, जिसमें राज्य सरकार से **मैतेई समुदाय** को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने पर विचार करने को कहा गया था। **कुकी** और अन्य जनजातियों ने इसका कड़ा विरोध किया।
- जनसांख्यिकी और भूमि का विवाद:**
  - मैतेई समुदाय:** राज्य की कुल आबादी का लगभग 53% हैं, जो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी (Imphal Valley) में रहते हैं। घाटी राज्य के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 10% है।
  - कुकी-नागा जनजातियां:** आबादी का लगभग 40% हैं, जो मुख्य रूप से राज्य के 90% पहाड़ी क्षेत्रों (Hills) में निवास करते हैं।
  - नियम कानून:** पहाड़ी इलाकों में गैर-जनजातीय लोगों (जैसे मैतेई) को जमीन खरीदने पर कानूनी रोक है, जबकि जनजातीय लोग घाटी में जमीन ले सकते हैं। मैतेई समुदाय का तर्क है कि ST दर्जा मिलने से वे अपने भूमि अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे, जबकि कुकी समुदाय को डर है कि इससे उनकी जमीन और नौकरियों में हिस्सेदारी छीन जाएगी।
- अवैध घुसपैठ और जंगलों से बेदखली:** राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वनों से अवैध बस्तियों को हटाने की कार्रवाई और पड़ोसी देश म्यांमार से हो रही घुसपैठ ने भी दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ाया।



# महत्वपूर्ण तथ्य



## 2. संघर्ष की शुरुआत और हिंसा

- **3 मई 2023:** ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (ATSUM) ने ST दर्जे के विरोध में एक 'आदिवासी एकजुटता मार्च' निकाला, जिसके दौरान चुराचांदपुर और बिष्णुपुर की सीमा पर झड़पें शुरू हुईं।
- **व्यापक हिंसा:** यह झड़प जल्द ही पूरे राज्य में जातीय हिंसा में बदल गई। दोनों समुदायों के बीच हथियारबंद संघर्ष हुए, घरों और पूजा स्थलों को जलाया गया।
- **हथियारों की लूट:** राज्य पुलिस बल और शस्त्रागारों (Armouries) से बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार लूटे गए, जिससे हिंसा का स्तर और बढ़ गया।

## 3. मानवीय और सामाजिक प्रभाव

- **विस्थापन:** लगभग 60,000 से अधिक लोग बेघर हुए और उन्हें राज्य के विभिन्न राहत शिविरों (Relief Camps) तथा पड़ोसी राज्यों (जैसे मिजोरम) में शरण लेनी पड़ी।
- **जान-माल का नुकसान:** सैकड़ों लोगों की जानें गईं और हजारों लोग घायल हुए।
- **भौगोलिक विभाजन (Internal Border):** राज्य व्यावहारिक रूप से दो हिस्सों में बंट गया—घाटी क्षेत्र मैतेई-बहुल और पहाड़ी क्षेत्र कुकी-बहुल बन गया। दोनों समुदायों का एक-दूसरे के क्षेत्र में जाना लगभग बंद हो गया।

## 4. केंद्र और राज्य सरकार के कदम

- **सुरक्षा बलों की तैनाती:** स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए असम राइफल्स, CRPF और सेना की भारी टुकड़ियां तैनात की गईं।
- **शांति समितियां और जांच:** केंद्र सरकार ने एक शांति समिति और हिंसा के कारणों की जांच के लिए आयोग का गठन किया।
- **AFSPA लागू करना:** राज्य के संवेदनशील हिस्सों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को फिर से लागू/विस्तारित किया गया।



# महत्वपूर्ण तथ्य



## AFSPA extended by six months in three States

### NEW DELHI

The Union Home Ministry on Friday extended the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) in parts of Manipur, Arunachal Pradesh, and Nagaland for another six months, following a review of the law and order situation there. » **PAGE 5**

## AFSPA extended in parts of Arunachal, Manipur, Nagaland

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

The Union Home Ministry on Friday extended the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) in parts of Manipur, Arunachal Pradesh, and Nagaland for another six months.

The AFSPA has been extended in the whole State of Manipur except the jurisdiction of 13 police stations in five valley districts, a notification said. Manipur has been affected by ethnic violence since May 3, 2023.

On November 14, 2024, out of 19 police stations in seven districts of Manipur, the Act was reimposed in the limits of six police stations in five districts, mostly in the valley, in the wake of the 2023 ethnic violence. President's Rule was imposed in the State on February 13, 2025 and revoked on February 4 this year.

The AFSPA was withdrawn from all valley police stations between April 1, 2022 and April 1, 2023 by the Manipur government

amid an improved security situation and a "large sense of security among general public". The provisions of the Act were withdrawn from the Imphal municipality area in 2004.

In Nagaland, the Act was extended for another six months in nine districts, and 21 police stations in five other districts, another notification said.

In Arunachal Pradesh, three districts and as many police stations in another district bordering Assam, were declared "disturbed area" for another six months.

### Sweeping powers

The 1958 law gives power to the Army and the Central Armed Police Forces deployed in "disturbed areas" to kill anyone acting in contravention of law; arrest and search any premises without a warrant; and protection from prosecution and legal suits without the Union government's sanction. The Act has been applicable in Manipur since 1981. Manipur, a former Union Territory, attained Statehood in 1972.

*Soluh*

*6 month*



# महत्वपूर्ण तथ्य

- AFSPA का पूरा नाम सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act) है। यह भारतीय संसद द्वारा 1958 में पारित किया गया एक विशेष कानून है, जो सुरक्षा बलों को "अशांत क्षेत्रों" (Disturbed Areas) में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।

## 1. यह कानून कहाँ और क्यों लागू होता है?

- AFSPA मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहाँ उग्रवाद (insurgency), अलगाववाद या बड़े पैमाने पर जातीय/हिंसक अशांति के कारण सामान्य कानून-व्यवस्था (Police) की स्थिति बिगड़ जाती है।
- प्रमुख क्षेत्र: पूर्वोत्तर भारत के राज्य (जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम का कुछ हिस्सा) और जम्मू एवं कश्मीर।

## 2. सुरक्षा बलों को मिलने वाले मुख्य अधिकार

- AFSPA के तहत सशस्त्र बलों (जैसे सेना, असम राइफल्स, CRPF) के अधिकारियों और जवानों को निम्नलिखित शक्तियाँ मिलती हैं:
- बिना वारंट गिरफ्तारी: किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस पर कोई संज्ञेय अपराध करने का संदेह हो।
- बिना वारंट तलाशी: किसी भी परिसर या घर में घुसकर तलाशी ली जा सकती है, यदि संदेह हो कि वहाँ अवैध हथियार या उग्रवादी छिपे हैं।

बल प्रयोग और गोली चलाने की अनुमति: यदि कोई व्यक्ति कानून या धारा 144 का उल्लंघन करता है, तो चेतावनी देने के बाद सुरक्षा बल उस पर गोली भी चला सकते हैं।

- संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार: उग्रवादियों के ठिकानों, बंकरों या गोला-बारूद के गोदामों के रूप में इस्तेमाल होने वाले ढाँचों को नष्ट किया जा सकता है।
- कानूनी संरक्षण (Legal Immunity): AFSPA के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों के जवानों पर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई नागरिक मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जा सकता।

## 3. "अशांत क्षेत्र" (Disturbed Area) क्या है?

- किसी क्षेत्र को AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने का अधिकार राज्यपाल, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होता है। एक बार अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद वहाँ कम से कम 6 महीने के लिए AFSPA लागू हो जाता है, जिसे समीक्षा के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है।



# महत्वपूर्ण तथ्य



## 4. AFSPA से जुड़ी चुनौतियाँ और विवाद

- मानवाधिकारों का हनन: आलोचकों का तर्क है कि इस कानून की आड़ में निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन, फर्जी मुठभेड़ और शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है।
- जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21): मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, यह अधिनियम संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
- जीवन की गाथा: मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने AFSPA को हटाने की मांग को लेकर 16 वर्षों तक (2000-2016) भूख हड़ताल की थी।

## जीवन रेखा / जीवनदान समीक्षा

- संतोष Hegde समिति (2013) और जीवन रेड्डी समिति (2005): इन समितियों ने समीक्षा की सिफारिश की थी। जीवन रेड्डी समिति ने AFSPA को रद्द करके इसके प्रावधानों को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) में शामिल करने का सुझाव दिया था।
- वर्तमान स्थिति: पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर के कई जिलों में उग्रवाद और हिंसा में कमी आने के बाद केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कई क्षेत्रों से AFSPA को आंशिक रूप से हटा लिया है। हालांकि, मणिपुर में हालिया जातीय हिंसा के कारण कुछ क्षेत्रों में इसे पुनः लागू या विस्तारित किया गया है।



# महत्वपूर्ण तथ्य



## 1. अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची - संघ सूची)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद को संघ सूची (Union List) में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।
- संघ सूची की प्रविष्टि 2 (Entry 2 of Union List): यह संसद को "केंद्र के सशस्त्र बलों (Armed Forces) के प्रयोग और तैनाती" पर कानून बनाने की शक्ति देती है। इसी शक्ति का प्रयोग करके AFSPA बनाया गया।

## 2. अनुच्छेद 355 (राज्य की सुरक्षा का कर्तव्य)

- अनुच्छेद 355 के तहत यह केंद्र सरकार (संघ) का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) और बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। AFSPA इसी कर्तव्य को पूरा करने का एक माध्यम है।

## सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (1997)

- जब AFSPA की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी (नागा पीपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ, 1997), तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया और स्पष्ट किया कि:
- यह अधिनियम अनुच्छेद 355 के तहत राज्य में आंतरिक अशांति से निपटने के लिए बनाया गया है।
- इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार से सलाह लेना अनिवार्य है, लेकिन अंतिम अधिकार केंद्र/राज्यपाल के पास है।

पु. नि. क. अधिकार

34



# महत्वपूर्ण तथ्य

## Congress leads nationwide stir seeking CEC's ouster and arrest

Modi and Shah using poll body chief to overcome public opposition through 'artificial manipulation', says Venugopal; party demands reversal of decisions taken by EC, including those related to SIRE; civil society groups hold parallel protests

The Hindu Bureau  
NEW DELHI

The Congress on Friday led nationwide protests demanding the resignation of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, accusing him of compromising the integrity of the country's electoral process, with the party's general secretary, K.C. Venugopal, seeking Mr. Kumar's resignation and arrest for alleged electoral malpractice. Civil society groups and other organisations held parallel protests in Delhi and several States.

Congress workers took to the streets across the country, with protests in several places being stopped by the police. Water cannons were used against demonstrators in Patna, Lucknow, and Punjab, while protesters were detained in Assam, Jammu, Odisha, Manipur, and other States. In Manipur's capital, Imphal, the police fired a few tear-gas shells to disperse the protesters.

In Kerala's Malappuram, Mr. Venugopal said the protests would continue until the CEC stepped down. Targeting Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, the Congress leader alleged that they were using Mr. Kumar to overcome public opposition to the government through "artificial manipulation".

**"Criminal offence"**  
"Resigning alone is not enough; he must be arrested. What he did is a criminal offence; he must be arrested," Mr. Venugopal said, adding that all decisions taken by Mr. Kumar,



**Raising concerns:** Youth Congress workers staging a protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, demanding his resignation, in New Delhi on Friday. SUSHIL KUMAR VERMA

including those relating to the special intensive revision, should be revoked.

The party's communication chief, Jairam Ramesh, said citizens and Congress workers hit the streets demanding accountability over the capture of their fundamental right to vote and the "Chief Election Commissioner's diabolical mischief". "The frightened Modi Govt. has cracked down on protesters and detained Congress leaders and workers, young citizens and students, and civil society activists - in so many places across the country," he wrote on X.

Congress leader Pawan Khera told a press conference: "We want to say to Gyanesh Kumar: It's done, bro. Heed Rahul Gandhi's advice - resign and turn approver."

The Congress accused the Election Commission of an "unprecedented attack" on voter equality, al-

leging that a specific 'Mark VIP' feature had been created in the BLO application.

CEC Kumar cancelled two scheduled meetings in Uttar Pradesh. Poll body sources said these were not linked to the protests and were routine decisions.

### Citizens' protest

At Jantar Mantar in New Delhi, the campaign drew participation from civil society activists and organisations. The All India Students' Association (AISA), along with civil society members, organised a protest demanding the arrest of Mr. Kumar. CPI(M) Liberation general secretary Dipankar Bhattacharya, AISA president Neha Bora, activist Yogendra Yadav, lawyer Prashant Bhushan, RJD MP Manoj Jha, activists Anjali Bhardwaj and Nandita Narain were among those who

participated. Several protesters, including Mr. Bhatnacharya and Mr. Yadav, were detained by the Delhi Police.

Delhi Congress chief Devender Yadav, who had organised a march from the Delhi Congress office to Nirvachan Sadan, the EC's headquarters, was also detained by the police. Another protest was called by the Students' Federation of India outside Nirvachan Sadan. The Indian Youth Congress separately staged a protest in Delhi.

New Delhi Deputy Commissioner of Police Sachin Sharma said protesters were detained as no permission had been sought or granted to hold the protest at these venues.

In Patna, the Bihar Congress marched towards the EC office but was stopped by the police using water cannons. Similar protests were reported in Lucknow, where Congress workers

led by State president Ajay Rai clashed with the police after being stopped. In Assam, State Congress president Gaurav Gogoi and other leaders were detained when they attempted to march towards the Chief Electoral Officer's office.

In Jammu, Congress MP and AICC general secretary Syed Naseer Hussain led the protest, with several senior party leaders participating in the demonstration.

The Congress has framed the protests around its "vote chori" campaign, alleging that the electoral roll revision process could exclude legitimate voters. The protests followed Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi's press conference on Thursday on the issue

RELATED REPORTS ON  
» PAGE 3

ECI  
CEC & EC  
प्रतिपक्ष, अधिकार, मोरारजी,  
प्रमुखता  
2023



# महत्वपूर्ण तथ्य

## Keralam urges Centre to limit eco-sensitive areas to forests

State govt. submits recommendations seeking resetting of ESA in Western Ghats; populated areas, farmlands and plantations should be excluded from the notification, says Minister

The Hindu Bureau  
THIRUVANANTHAPURAM

The Kerala government has urged the Centre to limit the Ecologically Sensitive Area (ESA) in its Western Ghats region to forest areas covering 8,590.69 sq. km.

M.G. Rajamanickam, Special Secretary, Environment and Climate Change, formally placed the State's recommendations and suggestions before the Centre on Thursday, Minister for Electricity and Environment Sunny Joseph said in Thiruvananthapuram on Friday. "Our stand is that populated areas, farmlands and plantations should be excluded and the ESA limited to forest re-



A view of the Kootickal village in Kottayam district, which has been included in the draft ESA notification. VISHNU PRATHAP

gions," Mr. Joseph said.

In 2013, the K. Kasturirangan Committee had proposed an ESA of 13,108 sq. km covering 123 villages in the State. This had sparked widespread protests. Following a study, the Union Ministry of Environ-

ment and Forests had issued a draft notification that reduced the area to 9,993.7 sq. km. The State wants the ESA to be brought down to 8,590.69 sq. km and the number of villages to 98.

If needed, Chief Minis-

ter V.D. Satheesan will lead a delegation to New Delhi to press the State's case, said the Minister, adding that Kerala is seeking a final notification from the Centre as all notifications issued from 2014 to July 2023 have been withdrawn.

### 'Unique' case

Kerala's case was "unique" given its small size but dense population and large forest cover (29.15% of total area), he said. The addition of another law to the existing stringent laws protecting the forest, environment, paddy fields and wetlands could adversely affect the State's development, agriculture and the everyday life of the people, the Minister added.

## Narrowed posture

Karnataka must not reject the full framework of eco-sensitive areas

The Kasturirangan Report bears a pro-development attitude that allows human occupation and a range of economic activity across the Western Ghats, yet the Karnataka Assembly unanimously repudiated its recommendations. A grievance concerned the accuracy of the remote-sensing and satellite data from 2012 that the Report uses to distinguish natural from human-dominated landscapes. Another concern was its recommendation that an entire revenue village be placed within an 'ecologically sensitive area' (ESA) if at least 20% of its area is sensitive. This could bring farmland and human settlements within the ESA even when sensitive areas occupy only a fraction of the village. Following the Centre's directive to States in 2013-14 to begin ground-truthing the Report's recommendations, Karnataka faced bipartisan opposition centered on concerns about livelihoods, with vested interests, including stakeholders of activities both the Gadgil and the Kasturirangan Reports restrict/ban such as mining, allegedly fanning fears of displacement. The State thus elected to resist the ESA framework. Although the Assembly's resolution proposes returning to the unfinished task of producing an alternative map, the government's posture also faces a wider challenge.

The Centre's interim directions in 2013 preserve some protection for the ecosystems that the State stewards, but for the government and the businesses within potential ESAs, the delay may prolong uncertainty over what forms of planned development will ultimately be permitted. Broadly, particular States confront the economic and political consequences of local resistance and foregone development while the country as a whole will capture much of the national benefit of conserving the Ghats, so States have an incentive to negotiate the ESAs' extent down. However, as of mid-2026, Gujarat was reportedly close to an agreement with the Centre, Tamil Nadu had no substantive disagreement, Kerala wanted to reduce its already ground-truthed 9,993 sq. km to 8,805 sq. km, and Maharashtra and Goa wanted 378 and 21 villages omitted, respectively. These instances of progress (such as they are), the Ghats' continuity across six States, and the Centre's 2024 decision to allow ESAs in the region to be notified State by State increase pressure on Karnataka without legally binding it to its neighbours' choices. Specifically, Karnataka's ability to continue rejecting the framework as a whole becomes harder to sustain if it does not also produce an equally considered alternative. Karnataka needs to reconcile the apprehensions of its farmers and workers with the responsibilities accruing to the State with the largest share (by area) of the proposed ESAs.

## YouTube Homework

- Western Ghat
- Eastern Ghat
- **ESA**



# महत्वपूर्ण तथ्य



गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन समिति और राज्यों के मुद्दे

## 1. गाडगिल समिति (2011)

- मुख्य फोकस: कड़ा और सख्त पर्यावरण संरक्षण।
- सिफारिश: पूरे पश्चिमी घाट का 64% हिस्सा **ESA** 'पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) घोषित किया जाए।
- प्रतिबंध: खनन (Mining), खदानों और नए थर्मल पावर प्लांट या बड़े बांधों पर पूर्ण प्रतिबंध।
- दृष्टिकोण: फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह से स्थानीय ग्राम सभाओं को मिले।

## 2. कस्तूरीरंगन समिति (2013)

- मुख्य फोकस: व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण।
- सिफारिश: पूरे क्षेत्र के बजाय केवल 37% हिस्से को ही ESA घोषित किया जाए।
- विभाजन: जमीन को दो भागों में बांटा—प्राकृतिक परिदृश्य (जंगल = संरक्षण) और सांस्कृतिक परिदृश्य (गांव/खेती = विकास की छूट)।
- प्रतिबंध: केवल खनन और भारी प्रदूषण फैलाने वाले (Red Category) उद्योगों पर रोक; बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं को शर्तों के साथ अनुमति।



# महत्वपूर्ण तथ्य



## 3. केरल और कर्नाटक के मुद्दे:

- केरल के मुद्दे:
  - सघन आबादी: केरल में ESA के दायरे में कई गांव, घर और चाय/रबर के बागान (Plantations) आ रहे हैं।
  - किसानों का डर: स्थानीय किसानों को डर है कि पाबंदियों के कारण उनकी आजीविका छिन जाएगी, खेती प्रभावित होगी और उन्हें बेदखल होना पड़ेगा।
- कर्नाटक के मुद्दे:
  - विकास रुकने का डर: राज्य का मानना है कि ESA लागू होने से सड़कें, बिजली, सिंचाई और विकास परियोजनाएं पूरी तरह ठप हो जाएंगी।
  - मांग: कर्नाटक विधानसभा ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और मांग की है कि ESA को केवल सरकारी जंगलों (Notified Forests) तक सीमित रखा जाए, कृषि या रिहायशी जमीन पर नहीं।



# महत्वपूर्ण तथ्य

## YouTube Homework

➤ RBI

### Economy resilient with downside risks from West Asia conflict: RBI bulletin

Ashokamithran T.  
MUMBAI

The Reserve Bank of India (RBI), in its monthly bulletin released late on Friday, stated that the Indian economy had stayed resilient despite global uncertainties rising from the West Asia crisis.

"The escalation of conflict in West Asia in September has led to a sharp increase in crude oil prices, reigniting concerns of a further disruption in global supply chains and build-up of inflationary pressures," the RBI stated.

#### Pressure on finances

"Alongside, the rise in sovereign yields in some of the major advanced economies has put pressure on government finances. Despite such a challenging global environment, the Indian economy recorded a strong GDP growth in Q1:2026-27," it said.

"High-frequency indicators through August reflected sustained demand with segments of industry and services sectors displaying resilience," the RBI added in the bulletin.

The central bank further flagged inflationary tendencies in the economy transmitting as crude prices have begun increasing again. "Headline CPI inflation picked up in August 2026. Core inflation excluding precious metals has also increased from ultra-low levels of recent



The central bank flagged inflationary tendencies in the Indian economy.

months," the RBI said.

Commenting on the foreign exchange reserves, the regulator said that the special deposit scheme for non-resident Indians (NRIs) led to a record high reserve position of \$766 billion as of September 18, 2026.

"The reserves provided cover for 11.2 months of goods imports [as on September 18] and more than 100% of the external debt outstanding as at end March 2026," the RBI stated in the bulletin.

FCNR B flows also led to an increase in system liquidity, which has resulted in quickening deposit growth potentially supporting the ongoing credit growth cycle. On the external front, the RBI said that India's financial and external sectors drew strength from the real economy, despite geopolitical tensions and weather-related uncertainties are acting as key downside risks.



# महत्वपूर्ण तथ्य



- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 25 सितंबर 2026 को अपना मासिक बुलेटिन (September 2026 Issue) जारी किया है।

## 1. भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति (State of the Economy)

- GDP वृद्धि (GDP Growth):** वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही है।
- मुद्रास्फीति (Inflation):** अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति (Headline Inflation) थोड़ा बढ़कर 4.8% हो गई, जिसकी मुख्य वजह खाद्य पदार्थों (विशेषकर प्याज और दालों), ईंधन और कोर घटकों में आई तेजी थी।
- विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves):** मजबूत एफडीआई (FDI) प्रवाह और चालू खाते के घाटे (CAD) में नियंत्रण के चलते देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल-टाइम हाई (All-time High) पर पहुंच गया है।
- व्यापार घाटा (Trade Deficit):** मजबूत निर्यात वृद्धि के कारण भारत के मर्चेडाइज व्यापार घाटे में कमी आई है।

## 2. क्रेडिट-डिपॉजिट अंतर (Credit-Deposit Divergence)

- क्रेडिट बनाम डिपॉजिट (CD Ratio):** बुलेटिन में बैंकों के लोन (Credit) और जमा (Deposit) के बीच के बढ़ते अंतर का विश्लेषण किया गया है।
- बैंकिंग तंत्र पर निष्कर्ष:** अध्ययन में स्पष्ट किया गया कि उच्च क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात (CD Ratio) अपने आप में बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी का संकेत नहीं है। आधुनिक मौद्रिक प्रणाली में बैंक जब ऋण देते हैं, तो उससे खुद-ब-खुद जमा का निर्माण होता है। बैंकों ने अपनी देनदारियों और पूंजी का कुशल प्रबंधन किया है।

## 3. निजी कॉर्पोरेट निवेश और आउटलुक (Private Corporate Investment)

- निजी पूंजीगत व्यय (Private Capex):** वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का अनुमानित पूंजीगत व्यय (Capex Pipeline) ₹3.2 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
- पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का दबदबा:** नए निवेश और परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (विशेषकर ऊर्जा/पावर सेक्टर) का रहा है। इससे पता चलता है कि निजी कंपनियां क्षमता विस्तार के लिए लगातार तैयार हैं।



# महत्वपूर्ण तथ्य



## YouTube Homework

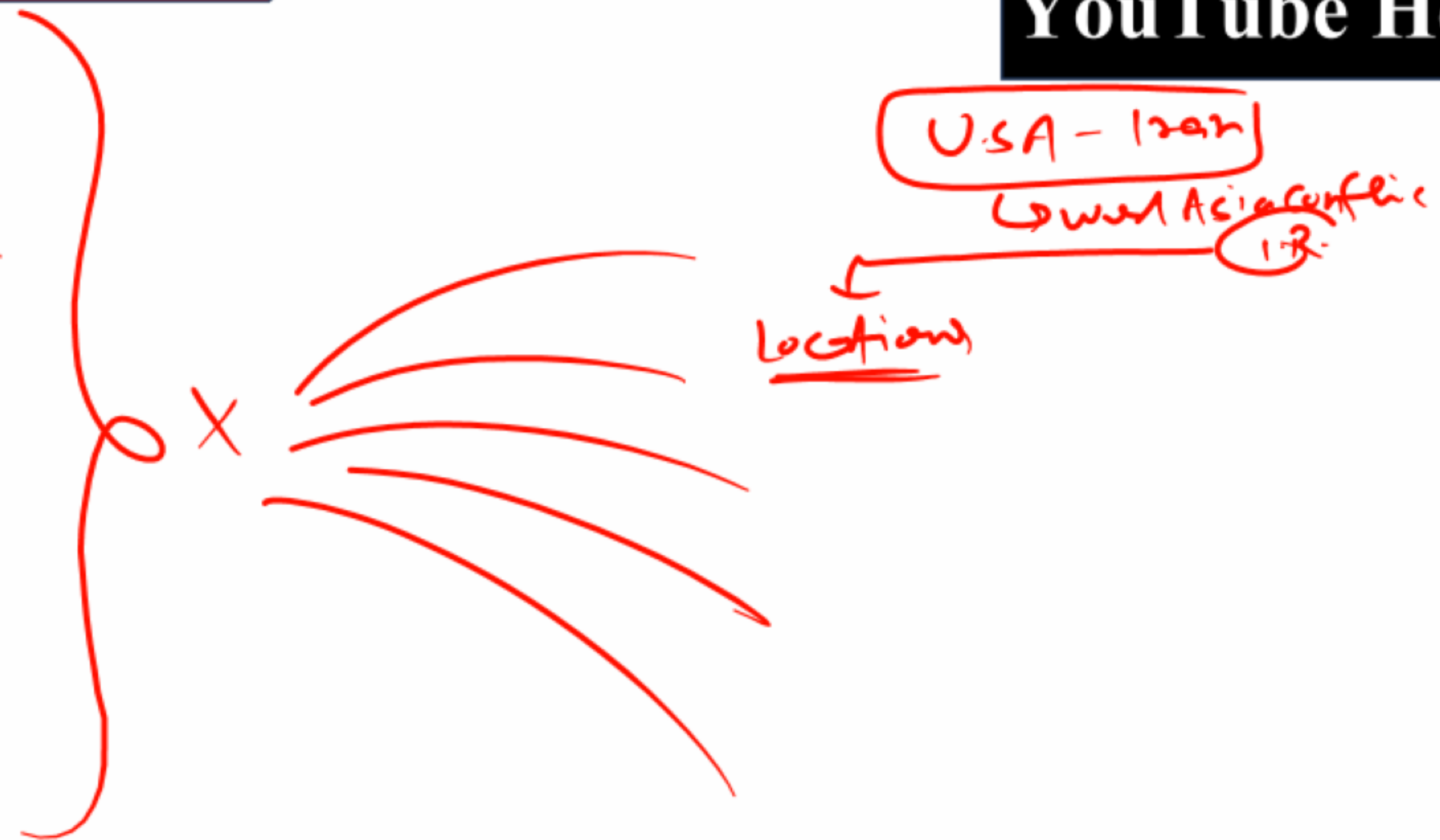
### Iran offers to reopen Hormuz if U.S. lifts blockade

**Associated Press**  
NEW YORK

Iran has offered to reopen the Strait of Hormuz and resume talks on its nuclear programme if the U.S. lifts its naval blockade, waives oil sanctions and observes a ceasefire, including in Lebanon. Foreign Minister Abbas Araghchi detailed the proposal in a private gathering on the sidelines of the UN General Assembly in New York, according to an attendee.

Trita Parsi, executive vice-president of the Quincy Institute think tank, who attended, said Mr. Araghchi suggested that a speedy agreement would help U.S. President Donald Trump ahead of November's midterm elections.

**FULL REPORT ON**  
» PAGE 12





# महत्वपूर्ण तथ्य





# महत्वपूर्ण तथ्य

## Poland halted border asylum claims, and now it wants the EU to follow suit

A temporary measure by Polish authorities to counter 'engineered and weaponised' migration emerges as blueprint for an EU-wide policy framework: legalising suspension of asylum could violate international law, critics say; EU's migration pact that took effect in July 'not enough', Polish Minister says

Associated Press  
WARSAW

When Poland stopped registering asylum applications from migrants entering from Belarus in March 2025, authorities presented it as a temporary emergency measure to counter what they saw as a push by Russia and its ally Belarus to destabilise the country by directing tens of thousands of migrants toward the European Union.

But the policy has remained in force for the past 18 months, and Poland is now urging the 27-nation bloc to allow temporary suspensions of asylum applications during episodes of "instrumentalised" mass migration elsewhere – a move that rights advocates warn could violate international law.

Since 2021, EU authorities have accused Belarusian President Alexander Lukashenko of weaponising migration by luring people to his country to find an easier entry point into the bloc than the more dangerous routes across the Mediterranean Sea.

**New framework**

The prospect of an EU-wide approach appeared to move closer on September 16, when European Commission President Ursula von der Leyen announced that the EU executive branch would soon propose a new "European emergency response framework" for cases of "engineered and weaponised" mass migration.

The new emergency framework would allow for "flexibility" in applying standard migration procedures under specific circumstances and for a limited period of time, she said.

Ms. Von der Leyen didn't specify what procedures would be made flexible. It's unclear what form this proposed framework would take, whether it would need approval from the EU Parliament and EU leaders, and how soon it might come into practice.

But Poland's Deputy Interior Minister in charge of migration, Maciej Duszczek, celebrated the announcement as a sign that Europe was becoming interested in what he calls "the Polish solution."

"We are happy that what we've been saying for a year, or a year and a half, is now becoming mainstream in the EU," Mr. Duszczek said.

He said that the July border crisis in Ceuta, when more than 70,000 people crossed from Morocco into the Spanish enclave in Africa, "made the EU realise" that other countries can be affected by similar border crises as Poland.



Ground zero: File photo of European Commission President Ursula von der Leyen and Polish Prime Minister Donald Tusk during their visit to the Polish-Belarus border, in Krzyni, Poland. AP

Tineke Strik, a Dutch member of the European Parliament, said that she fears Ms. von der Leyen's new emergency framework is indeed poised to take the Polish model EU-wide and legitimise the curtailing of asylum.

"If you normalise it, if you make it the default policy of all EU member states, you (the Poles) are not falling outside of the framework," Ms. Strik said. "It simply has been legalised."

"That would of course really undermine the core of the European and international asylum law – namely that people always must have the possibility to ask for asylum before they can be returned because

otherwise you don't know what will happen to them," she said.

**'Blow to human rights'**  
Michael O'Flaherty – the human rights commissioner for the Council of Europe, which is unrelated to the EU – said that the fact that the suspension of the right to asylum now appears in discussions at the EU level "worries" him because "it can very easily cross the line into a violation of international law."

Critics say legalising the suspension of asylum would constitute a major blow to fundamental human rights, particularly the principle of non-refoulement, which bars countries from returning

people to places where they may face persecution.

The principle was enshrined in the postwar refugee protection system after Jews and others fleeing Nazi persecution were refused safe haven during Second World War.

Mr. Duszczek said that the suspension of the right to asylum in Poland is fully compatible with international law and that people in the most vulnerable categories – pregnant women, children or those facing persecution in Belarus – can still apply for asylum even under the current system.

But the Polish ombudsman and nongovernmental organisations assisting migrants on the border

contradict the Minister. "Visibly pregnant women might stand a chance, but in the case of sick people or teenagers who are minors, their arguments are typically undermined," said Karolina Czerwinska from the Association for Legal Intervention, a Polish NGO offering legal aid to migrants.

Human rights groups said that Ms. Von der Leyen's announcement came as a surprise, because the EU's new Pact on Migration and Asylum, which took effect three months ago, already allowed countries faced with border crises to deviate from standard asylum procedures by extending deadlines for processing applications and holding migrants in detention for longer periods of time.

But Mr. Duszczek said that Ms. Von der Leyen's announcement meant that the European Commission recognised the new pact was "not enough" and that "we need a new instrument in EU law which guarantees that sometimes we can suspend normal procedures and have a sort of state of emergency."

The European Commission is expected to give more details during a summit of Interior Ministers on October 1, and discussions would continue during a European Council summit later that month.





# महत्वपूर्ण तथ्य

- Asian Games -  
Japan -  
Medals -  
81/13

प्रधानमंत्री कार्यालय

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर मनप्रीत कौर को बधाई दी

प्रतिष्ठि तिथि: 25 SEP 2026 9:17PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मनप्रीत कौर को एशियाई खेलों की शॉट पुट स्पर्धा में उनके शानदार प्रदर्शन और कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।

प्रधानमंत्री ने उनके शानदार ध्रो की सराहना की और उन्हें भविष्य की निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा:

"मनप्रीत कौर द्वारा शॉट पुट में शानदार प्रदर्शन!

उनके शानदार ध्रो ने उन्हें एशियाई खेलों में कांस्य पदक दिलाया है। मनप्रीत को बहुत-बहुत बधाई! भविष्य में उनकी निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं: पीएम @narendramodi"

PMO India @PMOIndia · Follow

A fine effort in shot put by Manpreet Kaur!

Her impressive throw has earned her a Bronze medal at the Asian Games. Congratulations, to Manpreet! Wishing her continued success: PM @narendramodi

9:02 PM · Sep 25, 2026

1.3K Reply Copy link

Read 46 replies

प्रधानमंत्री कार्यालय

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी

प्रतिष्ठि तिथि: 25 SEP 2026 9:15PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आइसो नागोया में आयोजित एशियाई खेलों की पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उत्तेजित किया कि इस प्रतियोगिता में इससे पहले जीते कांस्य पदक के बाद, वह पोलिथम पर लगातार देश का मान बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि उनका यह समर्पण और निरंतर प्रगति भारत के युवा डिस्टेंस रनर्स को प्रेरित करेगी।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा किया:

"पहले कांस्य और अब आइसो-नागोया में रजत पदक! गुलवीर सिंह एशियाई खेलों के पोलिथम पर देश को लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं।

पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई। उनका यह समर्पण और आगे बढ़ता प्रदर्शन भारत भर के युवा डिस्टेंस रनर्स को प्रेरित करेगी: पीएम @narendramodi"

प्रधानमंत्री कार्यालय

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बारानिका एलांगोवन को बधाई दी

प्रतिष्ठि तिथि: 25 SEP 2026 9:12PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने पहले एशियाई खेलों में ही महिला पोल वॉल्ट में कांस्य पदक जीतने पर बारानिका एलांगोवन को बधाई दी और इसे भारत के लिए एक विशेष पल व अनुकरणीय पदक बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, जो कई और युवा खिलाड़ियों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा:

"भारत के लिए एक विशेष उपलब्धि और एक यादगार पदक!

एशियाई खेलों में अपने पदार्पण पर ही महिला पोल वॉल्ट में कांस्य पदक जीतने पर बारानिका एलांगोवन को बहुत-बहुत बधाई। यह एक गर्व महसूस कराने वाली उपलब्धि है, जो कई और युवा एथलीटों को इस खेल में आगे आने के लिए प्रेरित करेगी: पीएम @narendramodi"

PMO India @PMOIndia · Follow

A special leap and an exemplary medal for India!

Congratulations to Baranica Elangovan on winning the Bronze in the women's pole vault at her Asian Games debut. A proud achievement that will inspire many more young athletes to take up the sport: PM @narendramodi

8:55 PM · Sep 25, 2026



# महत्वपूर्ण तथ्य

RIB

RIB  
Result Mitra

भारत सरकार  
पत्र सूचना कार्यालय

हमारे बारे में • प्रेस विशिष्टि • गैलरी • अनुसंधान इकाई • मीडिया सुविधाएं • आर्काइव • तथ्यों की जांच • उन्नत खोज

होम / सभी विशेषताएं / विशेषताएं विवरण

Infrastructure

## कचरे से लक्ष्य तक: प्लास्टिक की कहानी को फिर से लिख रहे हैं भारतीय शहर

Posted On: 25 SEP 2026 2:25PM

एक दशक पहले एक भारतीय बाजार में घूमते हुए, अक्सर एक प्लास्टिक बैग के साथ खरीदारी की जाती थी, जिसे आमतौर पर पॉलिथीन कहा जाता है। इन बैगों में सब्जियां, कपड़े, भोजन और अनगिनत अन्य खरीदारी होती थी।

आज देश भर के बाजार तेजी से प्लास्टिक मुक्त हो रहे हैं। कई खरीदार घर से कपड़े का पैला से जाते हैं। एक दुकान पर एक पुनः प्रयोज्य विकल्प प्रदान करता है। लोग घर पर सूखे और गीले कचरे को अलग करते हैं। घरों से एकत्र किया गया प्लास्टिक डंपसाइट के बजाय रिकवरी सेंटर में जाता है। पुनः प्रयोज्य नए उत्पाद के रूप में वापस आ सकते हैं। भारत ने सख्त नियमों और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ अपनी प्लास्टिक कहानी को बदलना शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गए **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)** ने संग्रह, पृथक्करण और पुनर्प्राप्ति के लिए प्रणालियों को मजबूत किया। 1 जुलाई 2022 से पहचानी गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक बस्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ है और न ही यह अकेले नियमों से आया है। यह छोटी-छोटी जागरूकता के माध्यम से विकसित हुआ है जो जागरूकता, स्थानीय कार्रवाई और सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित है। शहरों और समुदायों में वे दिखाते हैं कि कैसे छोटे परिवर्तन प्लास्टिक की यात्रा को नया आकार दे सकते हैं। इसके साथ ही वे प्लास्टिक की पूरी क्रिया प्रणाली को समाहित करते हैं कि किस प्रकार इसके इस्तेमाल को कम करें, पुनः उपयोग करें, वापसी, पुनर्प्राप्ति करें और पुनः बनाएं।

**कम उपयोग करना: बाजार को समाधान का हिस्सा बनाना**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 'स्वच्छता से सम्यता' सत्र का आयोजन किया

सत्र का आयोजन स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के अंतर्गत ब्रह्माकुमारीज़ के सहयोग से किया गया

सत्र में स्वच्छता, आंतरिक मूल्यों एवं जन-भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया

प्रतिष्ठि तिथि: 25 SEP 2026 7:39PM by PIB Delhi

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के 'मनन' सम्मेलन कक्ष में ब्रह्माकुमारीज़ के सहयोग से 'स्वच्छता से सम्यता' नामक एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया।

यह सत्र स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसे जन भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक पूरे देश में चलाया जा रहा है।





# महत्वपूर्ण तथ्य

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

रक्षा मंत्रालय

## भारतीय तटरक्षक बल 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन' के जरिए समुद्री सहयोग मजबूत करेगा

प्रविष्टि तिथि: 25 SEP 2026 7:25PM by PIB Delhi

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का जहाज 'शौनक' 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन' के तहत 25 सितंबर 2026 को चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के लिए रवाना होगा। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच समुद्री सहयोग तथा परिचालन के साथ आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छह 'सी राइडर्स'—भारत और जापान में दो-दो तथा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से एक-एक अधिकारी—'शौनक' पर सवार होंगे। ये अधिकारी आपसी तालमेल और सहयोग को बेहतर बनाने तथा परस्पर विश्वास को गहरा करने के उद्देश्य से जहाज पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं पेशेवर आदान-प्रदान के कार्यक्रम में शामिल होंगे।



यह पहल 26 मई, 2026 को जारी क्वाड विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान के अनुरूप है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्वाड देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

QUAD  
Quad-At-Sea Ship Mission,  
→ शौनक  
Ind - 2  
Jpn - 2  
USA - 1



# महत्वपूर्ण तथ्य



## भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह-2026

‘भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह (आईआईडब्ल्यू 2026) का 9वां संस्करण 22 सितंबर से 26 सितंबर, 2026 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय “जलवायु के अनुकूल जल प्रबंधन” है। जलशक्ति मंत्रालय ‘भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह’ का आयोजन करता है।

इस वर्ष की चर्चाएं सात उप-विषयों पर केन्द्रित हैं-

- समावेशी और न्यायपूर्ण जल प्रशासन
- जल ससाधनों के बेहतर सदुपयोग हेतु सहयोग
- जल सुरक्षा के लिए तकनीक और समुदाय
- जलवायु से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में जल
- जल संबंधी बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण हेतु वित्तपोषण का नवीन मॉडल
- जल ससाधन प्रबंधन
- लोगों और धरती के लिए जल



इस कार्यक्रम में छह केन्द्रीय मंत्रालयों और 16 राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि एक साथ आयेंगे। इसमें हिस्सा लेने हेतु लगभग 150 देशों को आमंत्रित किया गया है और 11 देशों के साझेदार देश के तौर पर शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में मंत्रियों के पूर्ण सत्र, युवा मंच और खास तौर पर स्टार्ट-अप के लिए मंच सहित जल क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर 49 विशेष सत्र होंगे।



# Home Assignment



1. IAEA

2. UNGA — 8/9

3. World Ozone Day — ✓



# Overview

- UNGA
- India's Nuclear Policy
- NPCI – UPI – MDR
- Manipur Crisis
- AFSPA
- ECI Issue – SIR
- Kasturiranjana Report
- RBI – Monthly Bulletin
- USA-IRAN Conflict
- Poland – Belarus Conflict
- Asia Games
- International Water Beat
- स्वच्छता से सभ्यता
- QUAD at Sea Ship

*Thank You*

*Result Mitra*

*Thank*



# Thanks For Watching

Follow us for more Updates



@RRESULTMITRAOFFICIAL



Join our Telegram



@SUNILVERMA\_THEIASMENTOR



Follow on Instagram



Subscribe Now

Stay Connected

Learn  
Share  
Grow  
Together ♥

Better  
Students  
Brighter  
Tomorrow

Small  
Steps  
Big  
Results  
😊

DISCIPLINE  
CONSISTENCY  
SUCCESS